साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 9, अंक : 41 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 29 मई 2024 से 4 जून 2024 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

क्यों चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता पर्यावरण ?

नई दिल्ली। भारत अभी चुनावी उत्सव में रंगा है। कई मामलों में लोकसभा का मौजूदा चुनाव विश्व का सबसे बड़ा चुनाव है। क्योंकि भारत विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला लोकतंत्र है, सबसे ज्यादा मतदाता (लगभग 97 करोड़) इस चुनाव में भाग ले रहे हैं और इस चुनाव में सफल हरेक प्रतिनिधि सबसे ज्यादा लोगों को, औसतन 18 लाख लोगों का संसद में प्रतिनिधित्व करेंगे। छह चरण के चुनाव बीत चुके हैं, पर मतदान का ग्राफ पिछले आम चुनाव के मुकाबले काफी कम है। कम मतदान के राजनैतिक मायने तलाशे जा रहे हैं पर प्रचंड गर्मी और हीटवेव की बढ़ती घटनाओं पर शायद ही मतदाता या राजनीतिक दलों का ध्यान हो। बीता अप्रैल आधिकारिक रूप से 1850 के बाद से सबसे गर्म अप्रैल साबित हुआ है। वर्तमान मई भी उसी राह पर है। और तो और साल 2023 अब तक का सबसे गर्म साल था ही। मतलब विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के चुनाव में मानवता के सामने की सबसे बड़ी चुनौतियां जो मानव के अस्तित्व का सवाल बनी हुई हैं, पर्यावरण का नाश, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, पानी, मिट्टी, नदी, जंगल आदि कोई मुद्दा नहीं है। ये न 56 मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के चुनावी नारों में दिख रहा है न ही किसी भी स्तर के राजनैतिक विमर्श में।

मौजूदा मतदाता और चुनाव क्षेत्र पर नजर डालें तो पाते हैं कि अधिकांश ज्वलंत चुनावी मुद्दों के मूल में प्रकृति के साथ हमारे नकारात्मक रूप से तेजी बदलते समीकरण ही तो हैं। हर दूसरा मतदाता किसान है, जिनके खेत या तो बाढ़, नहीं तो सुखाड़ या फिर उचित बाजार या फिर अन्य आपदा से प्रभावित है। हर आठवां मतदाता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जंगल पर निर्भर है और जंगल या तो साफ किए जा रहे हैं या फिर उनकी संरचना में बदलाव आ रहा है। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में पिछले तीस सालों में औसत जंगल के कम होने की दर ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर रही है। और कुछ नहीं तो पिछले कुछ हफ्तों से जल रहे उत्तराखंड, हिमाचल और यहां तक जम्मू कश्मीर के जंगल बानगी भर है। भले मौजूदा सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए प्रभावी ढंग से काम किया है, पर अभी भी एक बड़ी संख्या गरीबी रेखा के नीचे है, जिस पर बदलते मौसम और पर्यावरण के विघटन का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। यानी हर मतदाता तक बदलते जलवायु की धमक पहुंच रही है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) के अनुसार, पिछले तीन सालों में औसतन देश का हर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कम से कम मौसम की तीन चरम परिस्थितियों का शिकार हुआ है। ऐसा नहीं है कि आम जन को पृथ्वी पर मुश्किल होते हालात का अंदाजा नहीं है या पूरी तरह से बेखबर है। येल विश्वविद्यालय और सीवोटर के भारतीय मतदाता पर किए गए सर्वे में जलवायु परिवर्तन पर जागरुकता की बात स्पष्ट हो जाती है। हर छह में से पांच आदमी जलवायु परिवर्तन होने की पुष्टि करता है, हर पांच में से चार जलवायु परिवर्तन से चिंतित है और लगभग तीन-चौथाई मतदाता मौसमी बदलाव को महसूस करता हैं। आधे से अधिक लोग सरकार से जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार गैसों की कमी की अपेक्षा रखते हैं और समय के साथ-साथ जागरूक लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहली बार के शहरी मतदाता पर किए गए एक अन्य सर्वे के अनुसार, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। पर भारतीय मतदाता के बीच बढ़ती जागरुकता के बाद भी इतने महत्वपूर्ण के मुद्दे न मतदाता साध पा रहे हैं और न ही एक-एक मत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते राजनीतिक दल। पर्यावरण को लेकर अदद जागरुकता न सिर्फ मतदाता में है बल्कि राजनैतिक दल भी इसे खानापूर्ति के स्तर पर ही सही इसे चुनावी घोषणापत्र में शामिल जरूर ही कर रहे हैं। दो दशक पहले शायद ही कोई दल प्रदूषण, जैव-विविधता या जलवायु परिवर्तन की तरफ ध्यान भी देता था, पर ये मुद्दे मौखिक न सही कम से कम लुभावने वादों के साथ कागज पर इस बार अनेक पार्टियों की गारंटी में शामिल हैं। पिछले 2019 के आम चुनाव में कम से कम दो प्रमुख राजनैतिक दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को विशेष स्थान देना शुरू कर चुके थे जो इस बार भी जारी है। कम से कम पिछले दो आम चुनाव में मुख्य पार्टियों के घोषणापत्र में शामिल होने के बाद भी संसद में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। पिछले आम चुनाव से पहले के बीस साल में जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर मात्र एक प्रतिशत से भी कम सवाल उठाए गए और यही हाल अभी चल रहे चुनाव प्रचार में भी दिख रहा है। इस बार कई प्रमुख पार्टियों ने सधी शब्दावली के साथ इस मुद्दों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया है जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा, मुख्य विपक्षी कांग्रेस सहित कम्युनिस्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस शामिल हैं। खासकर भाजपा ने बड़े तकनीकी सलाहियत के साथ पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को समग्रता के साथ उचित स्थान दिया है। चाहे वो खेती किसानी से जुड़ा मिलेट का मुद्दा हो, सतत आर्थिक विकास हो, ऊर्जा से जुड़ा बायो एनर्जी, सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य हो, शहरी विकास से जुड़ा यातायात, ई व्हीकल, जल प्रबंधन हो, मिशन लाइफ हो, नमामि गंगे और नदी बेसिन प्रबंधन से जुड़े तमाम मुद्दों को शामिल कर एक पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते दिख रही है। वहीं कांग्रेस जिसके शासन में अधिकांश पर्यावरण से जुड़े कानून पारित हुए हैं, ने भी इस बार पर्यावरण, जलवायु, आपदा और जल प्रबंधन को अलग से 20 अलग-अलग वादों के रूप में स्थान दिया है और जलवायु संकट से बचाव के लिए अलग से प्राधिकरण और कोष बनाने का वादा किया है। कम्युनिस्ट पार्टी अपनी विचाधारा के अनुरूप ही सही जलवायु के मुद्दे को रखा है। जिन-जिन पार्टियों ने भी पर्यावरण को अपने घोषणापत्र में शामिल किया है उन सब में एक बात समान है कि सबने इस मुद्दे को आखिर में स्थान दिया है।

देश में मॉनसूनी बारिश के सामान्य से अधिक होने का अनुमान, जून में भी लू से नहीं मिलेगी राहत

नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दक्षिण-पश्चिम मॉनसून, वर्षा ऋतु, जिसका समय जून से सितंबर तक होता है, का पूर्वानुमान आउटलुक जारी किया है। मौसम विभाग के संवाददाता सम्मेलन में जून 2024 में होने वाली बारिश और तापमान का पूर्वानुमान भी जारी किया है।

मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसूनी बारिश लंबी अवधि के औसत (एलपीए) के 106 फीसदी तक हो सकती है। इस प्रकार, उन्होंने मॉनसून सीजन, 2024 के दौरान पूरे देश में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसूनी मौसम के दौरान मध्य भारत और भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में सामान्य से अधिक यानी एलपीए का 106 फीसदी तक बारिश होने का अनुमान है। वहीं, उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य यानी एलपीए के 92 से 108 फीसदी और पूर्वोत्तर भारत में एलपीए का 94 फीसदी यानी बारिश के सामान्य से कम होने के आसार हैं। महापात्र ने कहा कि चक्रवात %रेमल% ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में मॉनसून की प्रगति को आगे बढ़ाने में मदद की है, उन्होंने कहा कि इसका लंबे समय तक मॉनसून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। महापात्र ने कहा कि देश के अधिकांश बारिश पर निर्भर वाले हिस्सों में खेती मॉनसून कोर जोन (एमसीजेड) में दक्षिण-पश्चिम मॉनसूनी बारिश के सामान्य से अधिक, यानी एलपीए के 106 फीसदी से अधिक होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत के उत्तरी हिस्सों, पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत के पूर्वी भाग और पूर्वी भारत के आसपास के क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका जताई गई है, इन हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। जून, 2024 के दौरान पूरे देश में बारिश के सामान्य होने के सबसे अधिक आसार जताए गए हैं, यानी एलपीए का 92 से 108 फीसदी तक बारिश हो सकती है। जून के महीने में दक्षिण प्रायद्वीप के अधिकांश इलाकों और मध्य भारत के आसपास के अलग-अलग हिस्सों, उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं, जून महीने में उत्तर पश्चिम भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों और मध्य भारत के पूर्वी भाग के कई इलाकों, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बारिश के सामान्य से कम होने की आशंका जताई गई है।

कैसा रहेगा तापमान, कहां चलेगी हीटवेव या लू- जून के महीने में तापमान के पूर्वानुमान संबंधी अपडेट देखें तो, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान के सामान्य से कम रहने की संभावना है। वहीं देश के अधिकांश हिस्सों में मासिक अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार हैं।

उत्तर-पश्चिम भारत के सुदूर उत्तरी इलाकों और पूर्व तथा उत्तर-पूर्व भारत के कुछ हिस्सों में जून के महीने न्यूनतम तापमान के सामान्य से नीचे रहने का अनुमान है, वहीं, देश के अधिकांश हिस्सों में मासिक न्यूनतम तापमान के सामान्य से ऊपर रहने की आशंका जताई गई है। जून, 2024 के दौरान, उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों और मध्य भारत के आसपास के इलाकों में हीटवेव या लू वाले दिनों की संख्या सामान्य से अधिक होने के आसार हैं।

मौसम विभाग के अपने अपडेट में कहा है कि लू के दौरान, बुजुर्गों और स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों जैसी कमजोर आबादी को गर्मी से संबंधित बीमारियों के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। लंबे समय तक अत्यधिक गर्मी से बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ता है और निर्जलीकरण होता है। मौसम विभाग ने अधिकारियों को ठंडे या शीतलन केंद्र खोलकर, शहरी गर्मी वाले इलाकों में लोगों को गर्मी से बचाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने का भी सुझाव दिया है। विभाग ने कहा लू के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये कदम महत्वपूर्ण हैं। लू के दौरान सुरक्षित रहने के लिए लोगों को हाइड्रेटेड रहना होगा और अधिकतम ठंडे वातावरण में रहना होगा और चरम गर्मी के घंटों के दौरान भारी गतिविधियों से बचना होगा। भूमध्यरेखीय प्रशांत और हिंद महासागर में समुद्री सतह का तापमान (एसएसटी) स्थितियांइस वर्ष की शुरुआत में भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में देखी गई मजबूत अल नीनो की स्थितियां तेजी से कमजोर होकर कमजोर अल नीनो स्थितियों में तब्दील गई हैं और वर्तमान में ईएनएसओ तटस्थ स्थितियों की ओर बढ़ रही हैं। नवीनतम जलवायु मॉडल के पूर्वानुमानों से पता चलता है कि मॉनसून के मौसम की शुरुआत के दौरान ईएनएसओ-तटस्थ स्थितियां स्थापित होने की संभावना है। मॉनसून के मौसम के बाद के ला नीना स्थितियां विकसित होने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, वर्तमान में, हिंद महासागर पर तटस्थ हिंद महासागर द्विध्रुव (आईओडी) स्थितियां जारी हैं। कई वैश्विक जलवायु मॉडलों के नवीनतम पूर्वानुमानों से पता चलता है कि मॉनसून के मौसम के दौरान सकारात्मक आईओडी स्थितियां विकसित होने की संभावना है।

घर में यदि पाल रखा है इस प्रजाति का पक्षी, तो तुरंत करा लें रजिस्ट्रेशन वरना हो सकती है जेल

भोपाल- मध्य प्रदेश वन विभाग ने वन्यजीव संरक्षण कानूनों में एक महत्वपूर्ण संशोधन को लागू करने प्रक्रिया शुरु कर दी है। वन विभाग इस नियम के साथ अवैध तरीके से विदेशी पालतू जानवरों के स्वामित्व पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। यदि आपके पास अब बिना रजिस्ट्रेशन के अफ़्रीकी तोते की प्रजाति है तो आपको जेल हो सकती है। इस तोते का मालिक होना आपको बाघ के अवैध शिकार जितनी गंभीर मुसीबत में डाल सकता है। जिसके कारण आपको कई साल तक जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

अधिकारियों का कहना है कि सीआईटीईएस के तहत सूचीबद्ध जानवरों के सभी मालिकों को अगस्त 2024 तक सरकारी प्रक्रिया का पालन कर पंजीकरण कराना होगा ऐसा नहीं किए जाने पर मालिक के खिलाफ गंभीर कानूनी प्रकरण दायर किए जा सकते हैं। वन्यजीव अधिकारियों का कहना है कि उन्हे अभी तक केवल छह आवेदन ही प्राप्त हुए हैं, हालांकि मध्य प्रदेश में लाखों सीआईटीईएस-सूचीबद्ध जानवरों को पालतू जानवर के रूप में रखा जाता है। इसी अंतर के कारण विदेशी जानवरों की देश में कालाबाजारी की संभावना और अधिक बढ़ रही है।

वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम की धारा 49एम में संशोधन फरवरी 2024 में नोटिफाई किया गया। यह विशेष रूप से विदेशी पालतू जानवरों को पालने के रेगुलेशन और ट्रैकिंग को संबोधित करता है। सीआईटीईएस संशोधन एक बात पर विशेष जोर देता है। जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विलुप्त होने की कगार पर पहुंची प्रजातियों का संरक्षण शामिल है। अफ़्रीकन ग्रे तोते जिनको सिटाकस एरिथाकस भी कहते हैं नकल करने की क्षमता के कारण पालतू पशु प्रेमियों का पसंदीदा हो जाता है। जो उनके ब्लैक मार्केटिंग के खतरे को बढ़ाता है।

मालिकों को नियम के अनुसार परिवेश 2.0 पोर्टल parivesh.nic.in पर पंजीकरण कराना होगा। मालिक को अपने पालतू जानवर के जन्म, ट्रांसफर और मृत्यु की रिपोर्ट पशु चिकित्सा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ देनी होगी। उदाहरण के लिए कहे तो यदि तोता अंडा भी देता है तो इसकी सूचना भी देनी होगी । अधिकारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश ने धारा 49एम को लागू करने में आगे आकर संयोग दिया है।

चारधाम में बढ़ती भीड़ पर्यावरण के लिए खतरा, पिघल रहे ग्लेशियर

नई दिल्ली। चारधाम यात्रा की शुरुआत में ही उत्तराखंड हिमालय के चारों धामों में श्रद्धालुओं की अकल्पनीय भीड़ उमड़ रही है। इस साल पर्यावरणीय रूप से महत्वपूर्ण इन तीर्थों में 70 लाख से अधिक पर्यटक आ सकते हैं। इसकी कल्पना भी दो दशक पहले नहीं हुई थी।

सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में पिछले साल 56,31,224 यात्री पहुंचे थे, जबकि राज्य के गठन के वर्ष 2000 में 12,92,411 यात्री पहुंचे थे। 1968 में पहली बार बदरीनाथ में बस पहुंची, तो वहां लगभग 60 हजार लोग यात्रा करते थे। 1969 में गंगोत्री तक मोटर रोड बनाने और 1987 में भैरों घाटी का पुल बनाने पर वहां लगभग 70 हजार यात्री पहुंचते थे। हिमालयी धामों में वाहनों और यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ी है। पिछले वर्ष इन धामों पर 5,91,300 वाहन आए। हिमालय पर यात्रियों की इस महारैली से व्यवसायी खुश हैं क्योंकि यह उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है और पड़ोसी राज्यों को भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ पहुंचाता है। लेकिन अचानक बढ़ी हुई आस्था ने पर्यावरण और आपदा प्रबंधन क्षेत्र के लोगों को चिंतित कर दिया है। यात्रियों की बहुतायत से यात्रा मार्गों में गंदगी भी खूब हो रही है। मलजल शोधन संयंत्र (स्ञ्जक्र) जो इस मार्ग पर लगाए गए हैं, गंदगी को नदियों में डाल देते हैं और भीड़ बहुत अधिक है। इस वर्ष दस दिन की यात्रा में चारों तीर्थों तक 6.43 लाख यात्री और 60,416 वाहन पहुंचे थे। नवंबर तक यात्रा चलेगी साथ ही, इन वाहनों में सबसे ज्यादा प्रदूषण पैदा करने वाले डीजल वाहन हैं। काले कार्बन, जो ग्लेशियरों को पिघला रहा है और जलवायु परिवर्तन में भी योगदान दे रहा है, पर्यावरणविदों के लिए एक और चिंता का विषय है। ऑटोमोबाइलों द्वारा उत्सर्जित ब्लैक कार्बन बर्फ की सतहों पर जमा हो सकता है। गहरे रंग के कण हल्की सतहों की तुलना में अधिक सूर्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं, जिससे बर्फ और बर्फ का ताप बढ़ जाता है और ग्लेशियरों के पिघलने की गति तेज हो जाती है। जैसा कि जंगलों की आग ने पहले से ही वातावरण में ब्लैक कार्बन को बढ़ा दिया है, डीजल वाहन इसे और भी बढ़ा देंगे। पिछले वर्ष बदरीनाथ तक 2,69,578 वाहन आए थे, जबकि गंगोत्री तक 96,884 वाहन आए थे।इस वर्ष के दस दिनों में ही बदरीनाथ में 12,263 वाहन और गंगोत्री में 10,229 वाहन पहुंचे। ये दोनों धाम गंगोत्री और सतोपंथ ग्लेशियर समूहों में हैं, जो तेजी से पिघलने के कारण दुनिया भर में चिंता का विषय हैं। अलकनंदा और भागीरथी ग्लेशियर समूह गंगा की दो मुख्य धारा हैं। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उस वर्ष अप्रैल में इसरो ने जारी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमालयी ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के साथ ही ग्लेशियर झीलों की संख्या और आकार में लगातार वृद्धि हो रही है, जो आपदाओं के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। 676 झीलों में से 601 का आकार दोगुने से अधिक हो गया है, जबकि 10 झीलों का आकार 1.5 से दोगुना हो गया है और 65 झीलों का आकार 1.5 से दोगुना हो गया है, जैसा कि इसरो ने बताया है। गंगोत्री ग्लेशियर, जो लगभग 147 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, की खिसकने की गति 20 से 22 मीटर प्रतिवर्ष है, एक प्रसिद्ध ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉ. डीपी डोभाल ने बताया। अब कांवड़िए सीधे गोमुख जा रहे हैं, जबकि पहले दस साल तक वे हरिद्वार से ही गंगा जल भरकर लौटते थे। यही नहीं, गोमुख और गंगोत्री के बीच जेनरेटर लगाए गए हैं।

जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिये सभी नगरीय निकायों में 5 से 15 जून तक चलेगा विशेष अभियान

भोपाल (नगर प्रतिनिधि)मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में जल स्त्रोतों तथा नदी, तालाबों, कुओं, बावड़ियों एवं अन्य जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं इनके पुनर्जीवन के लिये 5 जून से 15 जून तक विशेष अभियान चलाया जायेगा। यह विशेष अभियान स्थानीय जन-प्रतिनिधियों, सामाजिक व अशासकीय संस्थाओं एवं जन अभियान परिषद की सहभागिता से चलाया जायेगा। अभियान के तहत विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से प्रदेश भर में मौजूद जल स्त्रोतों के स्थायी संरक्षण के लिये विभिन्न गतिविधियाँ की जायेंगी। अभियान के संचालन के लिये शहरी क्षेत्र में नगरीय विकास एवं आवास विभाग नोडल विभाग रहेगा।

प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग श्री नीरज मंडलोई ने इस विशेष अभियान के सुचारू संचालन एवं की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। श्री मंडलोई ने सभी कलेक्टर्स से कहा है कि अभियान के दौरान अमृत 2.0 योजनान्तर्गत प्रचलित जल संरचनाओं के उन्नयन का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से कराया जाये। अमृत 2.0 योजना अंतर्गत नगरीय निकाय में चयनित जल संरचनाओं के अतिरिक्त यदि कोई नदी, झील, तालाब, कुआं, बावड़ी उपलब्ध है, जिसके पुनर्जीवन/संरक्षण की जरूरत है, तो इनके उन्नयन कार्य स्थानीय सामाजिक एवं जनभागीदारी के माध्यम से कराये जायें। जल संरचनाओं में मिलने वाले गंदे पानी के नाले/नालियों को स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम 2.0) के अंतर्गत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना के माध्यम से डायवर्सन के बाद शोधित कर जल संरचनाओं में छोड़ा जाये। जल संरचनाओं के चयन के साथ ही इनके जीर्णोद्धार तथा नवीनीकरण के परिणाम संयोजित उद्?देश्यों जैसे - जलप्रदाय, पर्यटन, भू-जल संरक्षण, मत्स्य पालन, सिंघाड़े का उत्पादन आदि भी स्पष्टत= तय कर लिये जायें। जल संरचनाओं के चयन एवं उन्नयन कार्य में जीआईएस तकनीक का उपयोग किया जाये। नगरीय निकाय द्वारा मौके पर जाकर चिन्हित संरचनाओं की मोबाइल एप के जरिये जियो-टैगिंग कराई जाये। इस कार्य के लिये अमृत 2.0 योजना के तकनीकी सलाहकारों की मदद लें।

प्रमुख सचिव श्री मंडलोई ने कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार/उन्नयन कार्य में जनभागीदारी का सहयोग लें। इसके तहत जीर्णोद्धार/नवीनीकरण किये जाने वाले जल संग्रहण संरचना के कैचमेन्ट में आने वाले अतिक्रमण एवं अन्य गतिरोधों को दूर करना और जीर्णोद्धार/नवीनीकरण के कार्य में अपने अनुभवों के आधार पर नगरीय निकाय जनभागीदारी से सलाह लेकर उपयुक्त कार्यों का चयन किया जाये। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने एवं कार्य के क्रियान्वयन में भी आवश्यक सहयोग लिया जाये। कार्य क्रियान्वयन के दौरान जनभागीदारी श्रम, सामग्री, मशीनरी अथवा धनराशि के रूप में भी ली जा सकती है। जीर्णोद्धार/नवीनीकरण कार्य की सतत् निगरानी कर जीर्णोद्धार/नवीनीकरण के फलस्वरूप बढ़ी हुई जल भंडारण क्षमता के प्रयोजन एवं वितरण प्रणाली का निर्धारण किया जाये। श्री मंडलोई ने कहा है कि जल संरक्षण के जीर्णोद्धार/उन्नयन कार्य में कैचमेन्ट के अतिक्रमण हटाये जायें। कैचमेन्ट के उपचार जैसे- नाले/नालियों की सफाई अथवा इनका डायवर्सन सिल्ट ट्रैप, वृक्षारोपण, स्टार्म वाटर ड्रेनेज मैनेजमेन्ट इत्यादि, बंड विस्तार, वेस्ट वियर सुधार अथवा निर्माण, जल-भराव क्षेत्र में जमा मि?ट्टी अथवा गाद को निकालना, डि वीडिंग एरेशन, पिचिंग/घाट निर्माण कार्य किये जा सकते हैं। जल संग्रहण संरचनाओं से निकाली गई मिट्टी एवं गाद का उपयोग स्थानीय कृषकों के खेतों में किया जाये। जल संरचनाओं के किनारों पर यथासंभव बफर जोन तैयार किया जाये। इस जोन में हरित क्षेत्र/पार्क का विकास किया जाये। जल संरचनाओं के किनारों पर अतिक्रमण को रोकने के लिये फेंसिंग के रूप में वृक्षारोपण किया जाये तथा इनके संरक्षण के लिये सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से जागरूकता अभियान भी चलाया जाये। श्री मण्डलोई ने कहा है कि जल संरचनाओं के आस-पास किसी भी प्रकार सूखा अथवा गीला कचरा फेंकना सख्ती से प्रतिबंधित किया जाये। प्रतिबंधित गतिविधियों के लिये सूचना प?ट्टी लगाई जाये।

पांच दशकों में प्रवासी मछलियों में आई 81 फीसदी की विनाशकारी गिरावट, बढ़ता इंसानी प्रभाव रहा जिम्मेवार

नई दिल्ली जीवों का प्रवासन प्रकृति के अद्भुत आश्चर्यों में से एक है, लेकिन समय के साथ अपने अस्तित्व के लिए लम्बी यात्राएं करने वाले इन जीवों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। इससे न केवल धरती बल्कि मीठे पानी में पाई जाने वाली मछलियां भी सुरक्षित नहीं हैं।

एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले कुछ दशकों में मीठे पानी में पाई जाने वाली प्रवासी मछलियों की आबादी तेजी से घट रही है। इनमें सैल्मन, ट्राउट, ईल और स्टर्जन जैसी मछलियां शामिल हैं, जो अपने जीवन के विभिन्न चरणों में लम्बी यात्राएं करती हैं।

यह प्रवासी मछलियां अपने अस्तित्व के लिए मीठे पानी की धाराओं, नदियों पर निर्भर करती हैं। अपने प्रवास के दौरान इनमें से कुछ मछलियां लंबी यात्राएं करती हैं। यह छोटी धाराओं से लेकर बड़ी नदियों तक कभी-कभी तो पूरे महाद्वीप को पार कर उसी धारा में लौट आती हैं, जहां वे पैदा हुई थी। बता दें कि बहामास के निकट अपने प्रजनन स्थल तक पहुंचने के लिए यूरोपीय ईल दो वर्षों में करीब 10,000 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है। ऐसे में इन मछलियों की आबादी में आती गिरावट न केवल मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रही है, साथ ही इसके चलते लाखों लोगों की खाद्य सुरक्षा और जीविका पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं।

साफ पानी में पाई जाने वाली प्रवासी मछलियों पर जारी लिविंग प्लैनेट इंडेक्स 2024 के नवीनतम अपडेट के मुताबिक 1970 के बाद से मीठे पानी में पाई जाने वाली प्रवासी मछलियों की आबादी में 80 फीसदी से अधिक की गिरावट आई है। मतलब की इनमें हर साल औसतन 3.3 फीसदी की दर से गिरावट आ रही है।

यह इंडेक्स और उससे जुड़ी रिपोर्ट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन), जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, वर्ल्ड फिश माइग्रेशन फाउंडेशन, द नेचर कन्जर्वेंसी, वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फण्ड और वेटलैंड्स इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई है। इस इंडेक्स में मीठे पानी में पाई जाने वाली प्रवासी मछलियों की 284 प्रजातियों को ट्रैक किया गया है।

इस बारे में जारी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सभी क्षेत्रों में इन प्रवासी मछलियों की आबादी में गिरावट आ रही है। लेकिन दक्षिण अमेरिका और कैरीबियाई क्षेत्रों में यह सबसे तेजी से घट रही है, जहां पिछले 50 वर्षों में इन प्रजातियों की आबादी में 91 फीसदी की गिरावट आई है। गौरतलब है कि यह वो क्षेत्र है जहां दुनिया में मीठे पानी का सबसे बड़ा प्रवास होता है, लेकिन बढ़ती इंसानी महत्वाकांक्षा के चलते जिस तरह नदियों बांध, खनन और धाराओं को मोड़ने के लिए चलाई जा रही परियोजनाओं के चलते पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो इन मछलियों की आबादी में गिरावट की वजह बन रहा है।

वहीं यूरोप में मीठे पानी में पाई जाने वाली प्रवासी मछलियों की आबादी में गिरावट का यह आंकड़ा 75 फीसदी दर्ज किया गया है। उत्तर अमेरिका से जुड़े आंकड़ों पर गौर करें तो इनकी आबादी में 35 फीसदी की जबकि एशिया और ओशिनिया में 28 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अफ्रीका में इन मछलियों की क्या स्थिति है, वो आंकड़ों की कमी के चलते स्पष्ट नहीं है।

रिपोर्ट के मुताबिक पिछले तीन दशकों से इन मछलियों की आबादी में गिरावट की प्रवृत्ति लगातार बनी हुई है। यदि वैश्विक स्तर पर इनकी प्रजातियों के रुझान देखें तो जहां 65 फीसदी प्रजातियों में गिरावट आई है, वहीं 31 फीसदी में वृद्धि हुई है।

इतिहास पर नजर डालें तो यह मछलियां सदियों से प्राकृतिक चुनौतियों से जूझने के बाद भी अपने अस्तित्व को बचाए रखने में सफल रहीं हैं। लेकिन जिस तरह इंसानी गतिविधियों के चलते इनका प्रवासन बाधित हो रहा है उसका खामियाजा इनकी गिरती आबादी के रूप में सामने आ रहा है।

दरअसल, यह प्रवासी प्रजातियां इतनी लंबी दूरी तक यात्राएं करती हैं, ऐसे में उन्हें अपने लंबे सफर के दौरान मानव निर्मित अनगिनत बाधाओं और खतरों से निपटना पड़ता है। ऊपर से बदलती जलवायु और प्रदूषण नई चुनौतियां पैदा कर रहा है।

अपनी यात्रा के दौरान इन जीवों को आराम और भोजन की जरूरत होती है, लेकिन जिस तरह प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। उसकी वजह से इन्हें पर्याप्त आहार नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में थकान और भूख से उनकी मौत हो सकती है।

आंकड़ों की माने तो आज मीठे पानी की करीब एक तिहाई प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि यह खतरा प्रवासी मछलियों पर कहीं ज्यादा है। देखा जाए तो इनके प्रवास के लिए धाराओं, नदियों का उन्मुक्त प्रवाह जरूरी है, लेकिन जिस तरह इन नदियों को नुकसान हो रहा है, बांध जैसी बाधाएं खड़ी की जा रही हैं और प्रवाह में गिरावट आ रही है, वो इनके अस्तित्व के लिए खतरा बन रहा है। उदाहरण के लिए यूरोप में नदियों के उन्मुक्त बहाव की राह में बांध जैसी करीब 12 लाख बाधाएं मौजूद हैं।

इसी तरह नदियों में बढ़ता प्रदूषण, इनका बेतहाशा होता शिकार और जलवायु में आता बदलाव भी इन प्रजातियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। नदियों में पानी की उपलब्धता का समय और मात्रा भी इनके प्रवासन के पैटर्न को प्रभावित कर रहा है।

इनकी गिरावट के लिए जिम्मेवार अन्य कारकों में शहरों और उद्योगों से निकला गन्दा पानी और खेतों से बहकर आने वाला पानी जिम्मेवार है, जिसमें हानिकारक कीटनाशक मौजूद होते हैं। इसी तरह जलवायु में आते बदलावों के चलते इनके आवास और पानी की उपलब्धता पर असर पड़ रहा है, जो इनके लिए खतरा बन रहा है।

इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) ने अपने एक अन्य विश्लेषण में कहा है कि वैश्विक स्तर पर ताजे पानी में पाई जाने वाली मछलियों की करीब एक चौथाई प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा प्रवासी प्रजातियों पर कहीं ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि इसके लिए प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे कारण जिम्मेवार हैं।

ऐसे में रिपोर्ट में इनकी निरंतर निगरानी के साथ-साथ नदियों के उन्मुक्त बहाव को बहाल करने पर जोर दिया है। इनके संरक्षण के प्रयासों पर ध्यान देना भी जरूरी है। साथ ही इन प्रजातियों के प्रवास के दौरान रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करना भी महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन जो आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, उसके प्रभावों को सीमित करने के लिए उत्सर्जन पर लगाम जरूरी है।

इसी तरह बढ़ते प्रदूषण और नदियों की जल गुणवत्ता में आती गिरावट से निपटना न केवल इन प्रजातियों बल्कि स्वयं इंसानों के अस्तित्व के लिए भी बेहद जरूरी है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008